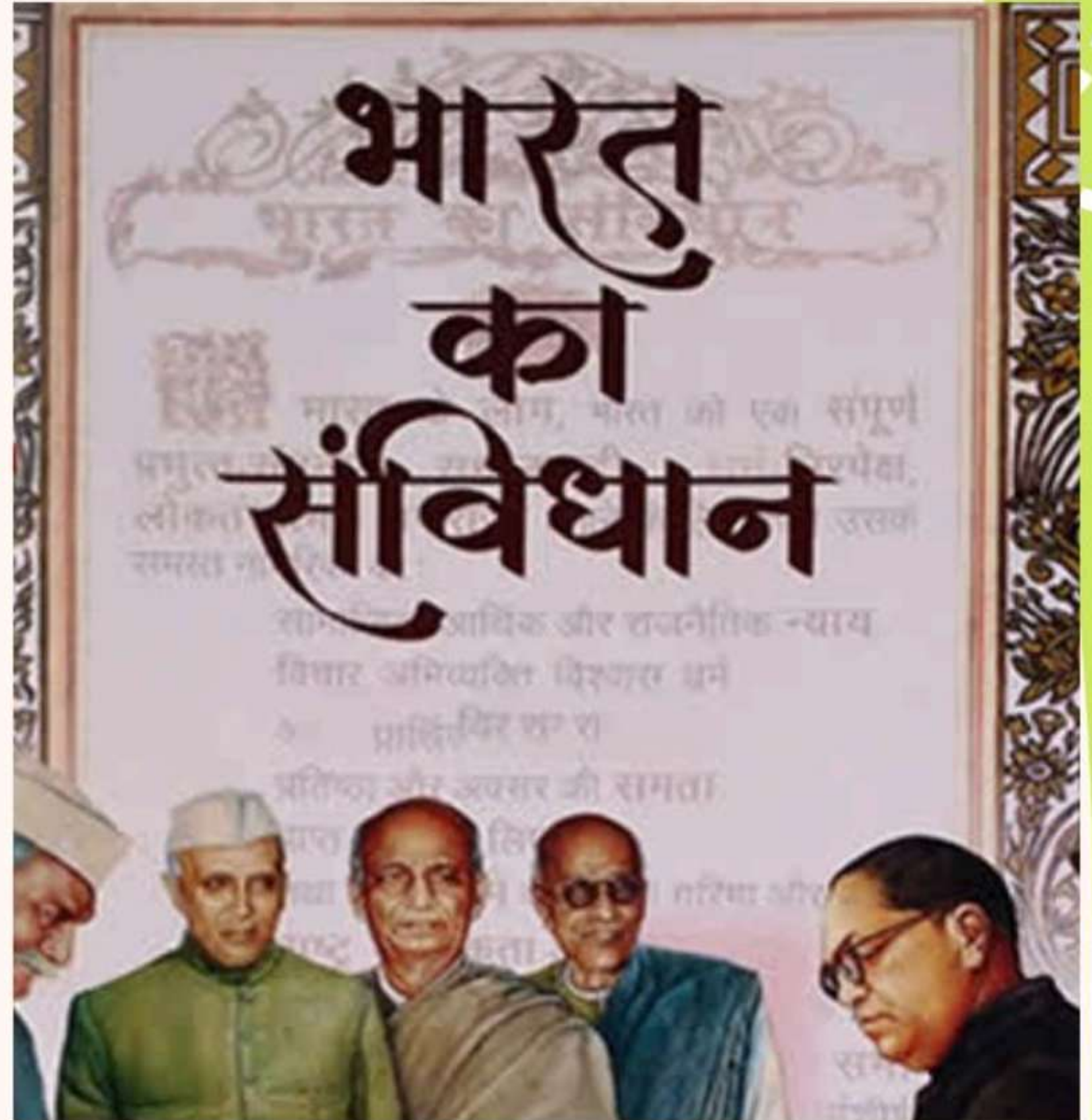
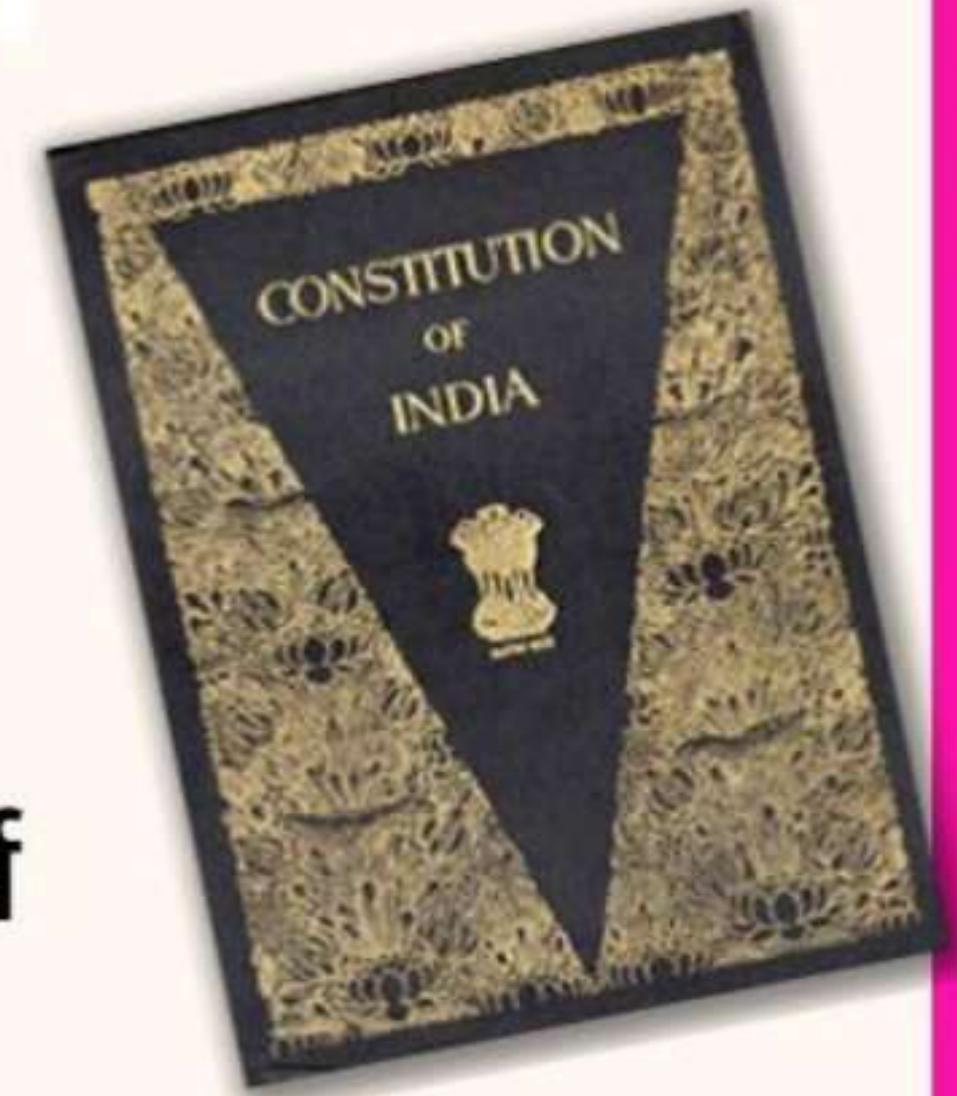


Important Constitutional Amendments of India

भारत के महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन



- The Constitution of India is dynamic and can be amended under Article 368. / भारत का संविधान गतिशील है और अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन किया जा सकता है।
- Amendments reflect changing social, political, and economic needs. / संशोधन बदलती सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आवश्यकताओं को दर्शाते हैं।
- As of 2025, over 100 amendments have been made. / वर्ष 2025 तक 100 से अधिक संशोधन किए जा चुके हैं।



Early Amendments (प्रारंभिक संशोधन)

- 1st (1951): Added 9th Schedule, special provisions for backward classes. / 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए।

- 7th (1956): Reorganization of States on linguistic basis; creation of Union Territories. / राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन; केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण।

Principally
State
Enacted.



Strengthening Parliament's Power (संसद की शक्ति को मजबूत करना)

- **24th (1971):** Parliament can amend any part of the Constitution and made it mandatory for the president to assent to constitutional Amendments. / संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है और राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधनों को सहमति देना अनिवार्य कर दिया है।
- **26th (1971):** Abolished Privy Purses and royal privileges. / रियासतों के प्रिवी पर्स और शाही विशेषाधिकार समाप्त किए गए।



Major Structural Changes (प्रमुख संरचनात्मक परिवर्तन)

- 36th (1975): Sikkim became 22nd State. / सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना।
- 42nd (1976): 'Mini Constitution' - added Socialist, Secular, Integrity; added Fundamental Duties. / 'लघु संविधान' - समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए; मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया।
- 44th (1978): Restored Fundamental Rights; Right to Property became Legal Right (Article 300A). / मौलिक अधिकारों को पुनर्स्थापित किया गया; संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार (अनुच्छेद 300A) बनाया गया।

→ Preamble

Art. 31



Strengthening Democracy

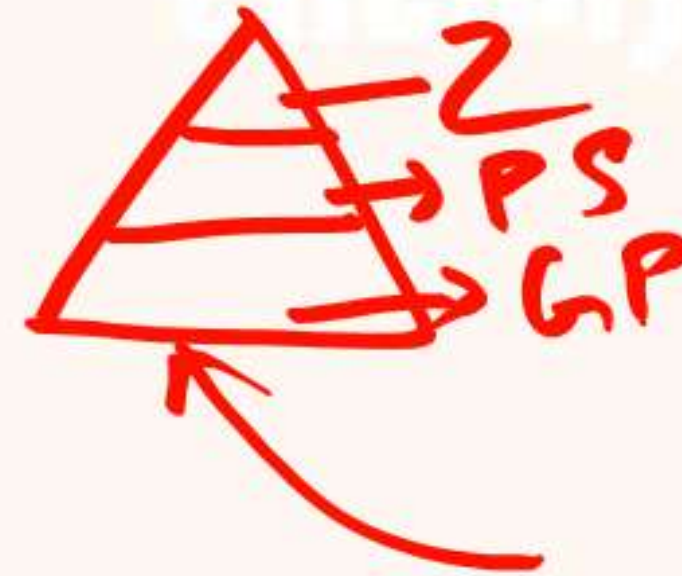
(लोकतंत्र को मजबूत
करना)

- 52nd (1985): Anti-Defection Law (10th Schedule). /
दलबदल विरोधी कानून (10वीं अनुसूची)।
- 61st (1989): Reduced voting age from 21 to 18. /
मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई।
- 69th (1991): Delhi became National Capital Territory. / दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया।



Grassroots Governance (जमीनी स्तर पर)

- 73rd (1992): Panchayati Raj (Part IX). / पंचायती राज व्यवस्था (भाग IX) से संबंधित।
- 74th (1992): Urban Local Bodies / Municipalities (Part IXA). / शहरी स्थानीय निकाय / नगरपालिकाओं (भाग IXA) से संबंधित।



Education & Social Welfare

(शिक्षा और समाज कल्याण)

- 86th (2002): Education made Fundamental Right for children aged 6 to 14 years (Article 21A). / शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए (अनुच्छेद 21A)।
- 91st (2003): Limited size of Council of Ministers. / मंत्रिपरिषद के आकार पर सीमा निर्धारित की गई।

MCD

Max 15% 50 100



Modern Reforms (आधुनिक सुधार)

- 101st (2016): Introduced GST. / वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू किया गया।
- 102nd (2018): NCBC became a Constitutional Body (Article 338B). / राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा दिया गया (अनुच्छेद 338B)।
- 103rd (2019): 10% Reservation for EWS. / आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10% आरक्षण प्रदान किया गया।
- 104th (2020): Extended SC/ST reservation till 2030; ended Anglo-Indian reservation. / अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षण 2030 तक बढ़ाया गया; एंग्लो-इंडियन आरक्षण समाप्त किया गया।
- 105th (2021): Restored States' power to identify OBCs. / राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की पहचान करने की शक्ति पुनः प्रदान की गई।
- 106th (2023): Reserves one-third of seats for women in the Lok Sabha, State Legislative Assemblies, and the Delhi Legislative Assembly. / लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों का आरक्षण करता है।

- Amendments ensure the Constitution remains relevant and progressive. / संशोधन यह सुनिश्चित करते हैं कि संविधान प्रासंगिक और प्रगतिशील बना रहे।
- They balance rights, duties, and governance efficiency. / ये अधिकारों, कर्तव्यों और शासन की दक्षता के बीच संतुलन बनाए रखते हैं।
- Reflect India's democratic evolution and social justice values. / ये भारत के लोकतांत्रिक विकास और सामाजिक न्याय के मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हैं।



“The Constitution is not a mere lawyer’s document, it is a vehicle of life.”

“संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज़ नहीं है, यह जीवन का साधन है।”

– B. R. Ambedkar



Constitutional Borrowings in the Indian Constitution

**भारतीय संविधान में
संवैधानिक उधार**



Warner & Spencer

- The Indian Constitution is the lengthiest written Constitution in the world. / भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है।
- It is a blend of various constitutional features from across the globe. / यह विश्व के विभिन्न संविधानों की विशेषताओं का समन्वय है।
- Represents 'unity in diversity' in both spirit and structure. / यह आत्मा और संरचना दोनों में 'विविधता में एकता' का प्रतीक है।



Why Borrow?

- To adopt tested principles of governance. / शासन के परीक्षित सिद्धांतों को अपनाने के लिए।
- To ensure administrative efficiency. / प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करने के लिए।
- To reflect democratic and federal ideals. / लोकतांत्रिक और संघीय आदर्शों को प्रतिबिंबित करने के लिए।
- To suit India's unique social and cultural diversity. / भारत की विशिष्ट सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता के अनुरूप बनाने के लिए।



From the Government of India Act,

From Govt Act 1935 ✓ 1935

- Federal scheme, Judiciary, Governors, Public Service Commissions. / संघीय ढांचा, न्यायपालिका, राज्यपाल, लोक सेवा आयोग।
- Emergency provisions. / आपातकालीन प्रावधान।
- Office of Governor. / राज्यपाल का पद।
- Administrative framework of Centre and States. / केंद्र और राज्यों की प्रशासनिक संरचना।



From the British Constitution



- Parliamentary system of government. / संसदीय शासन प्रणाली।
- Rule of law. / विधि का शासन।
- Bicameralism (Lok Sabha & Rajya Sabha). / द्विसदनीय व्यवस्था (लोकसभा और राज्यसभा)।
- Single citizenship. / एकल नागरिकता।
- Cabinet system and collective responsibility. / मंत्रिमंडल प्रणाली और सामूहिक उत्तरदायित्व।
- Speaker's office and parliamentary procedures. / लोकसभा अध्यक्ष का पद और संसदीय कार्यविधियाँ।
- Prerogative writs. / विशेषाधिकार रिट।

From the U.S. Constitution



- ✓ Fundamental Rights (Bill of Rights). / मौलिक अधिकार (अधिकारों का विधेयक)।
- ✓ Independence of Judiciary and Judicial Review. / न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनर्विलोकन।
- ✓ Impeachment of the President. / राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया।
- ✓ Removal of Supreme Court and High Court judges. / उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया।
- ✓ Post of Vice President. / उपराष्ट्रपति का पद।

From the Irish Constitution

Part IV
36-51

- Directive Principles of State Policy (DPSPs). /
राज्य के नीति निदेशक तत्व (डीपीएसपी)। ✓✓
- Nomination of members to Rajya Sabha. / (12)
राज्यसभा में सदस्यों के नामांकन की व्यवस्था।
- Method of election of the President (Indirect). /
भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया की प्रणाली (परोक्ष
चुनाव)। ✓✓



From the Canadian Constitution

- Federation with a strong Centre. / एक सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था।
- Residuary powers with Centre. / अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास निहित।
- Appointment of Governors by Centre. / राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा।
- Advisory jurisdiction of Supreme Court. / सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी अधिकार क्षेत्र।

Residuary list



From the Australian Constitution

- Concurrent List. / समवर्ती सूची।
- Freedom of trade and commerce. / व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता।
- Joint sitting of Parliament. / संसद का संयुक्त अधिवेशन।

Art 108



From the Soviet (USSR) Constitution

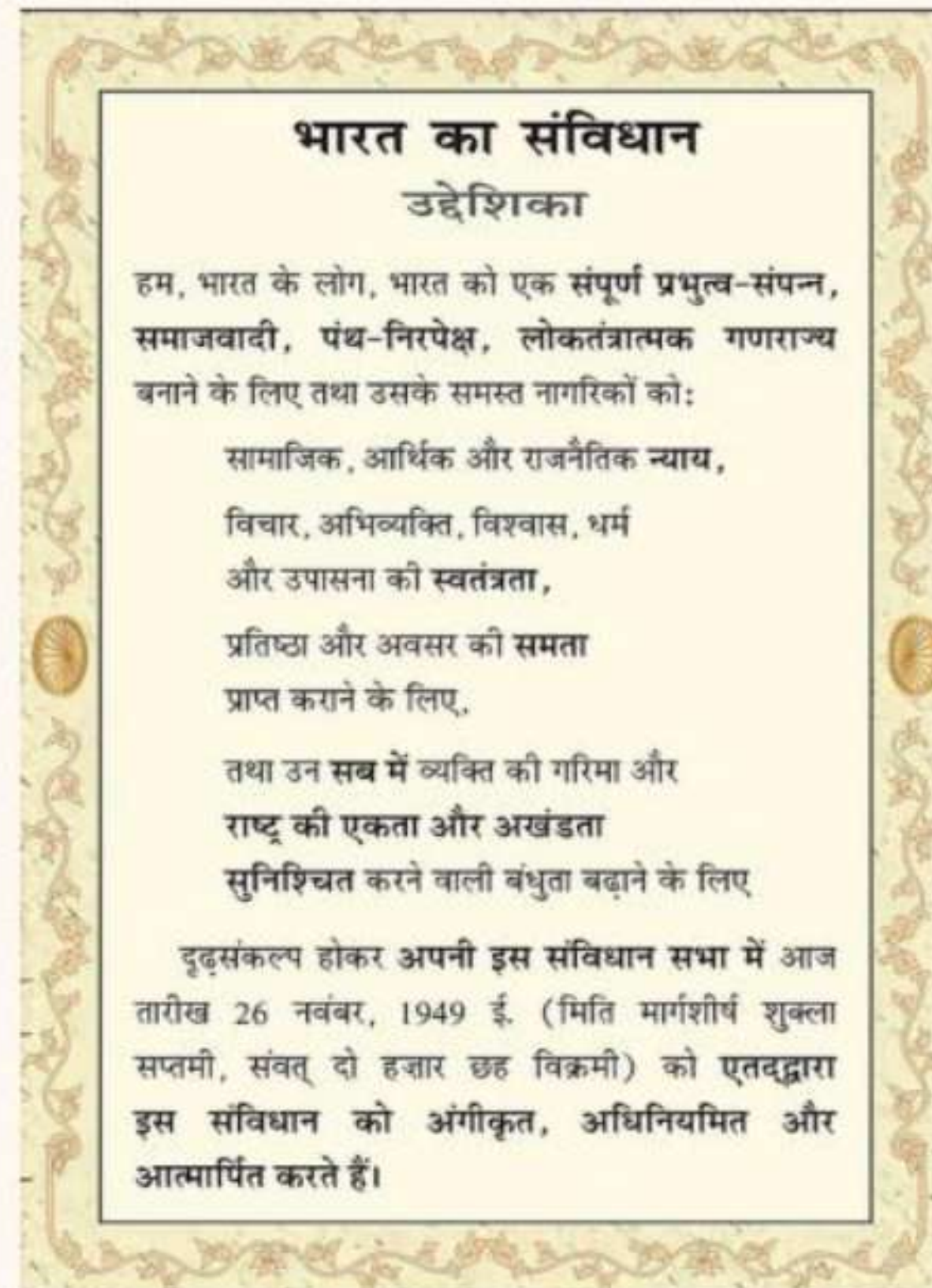
- Fundamental Duties. / मौलिक कर्तव्य।
- Ideals of Justice, Socialism in the
Preamble. / प्रस्तावना में न्याय और समाजवाद के
आदर्श।

कुछ



From the French Constitution

- Ideals of Liberty, Equality, and Fraternity in Preamble. / प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श।
- Republican form of Government. / गणराज्यात्मक शासन प्रणाली।



From the German (Weimar) Constitution

- Suspension of Fundamental Rights during
Emergency. / आपातकाल के दौरान मौलिक
अधिकारों का निलंबन।



From the South African Constitution

- Procedure for Amendment of Constitution. / संविधान में संशोधन की प्रक्रिया।
- Election of Rajya Sabha members (Proportional Representation). / राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव (अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा)।

368



From the Japanese Constitution

- Concept of 'Procedure Established by Law'. / 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' की अवधारणा।

Articles



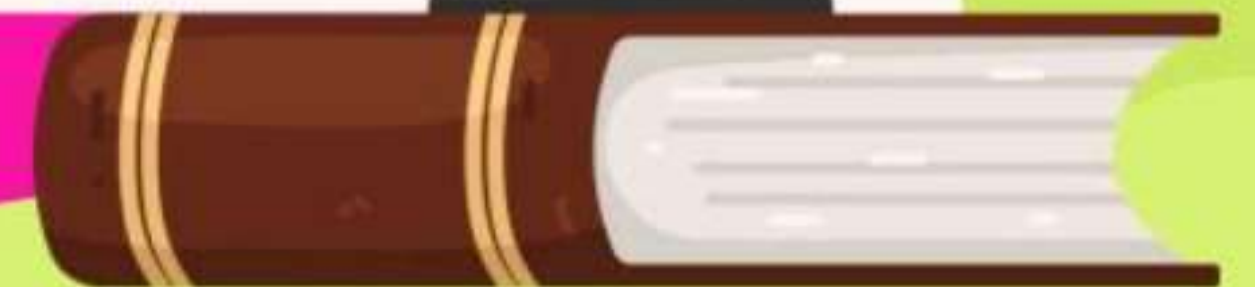
Summary

- **U.K. :** Parliamentary system, Rule of law, Bicameralism. / संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, द्विसदनीय व्यवस्था।
- **U.S.A. :** Fundamental Rights, Judicial Review. / मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन।
- **Ireland :** DPSPs, President's election. / राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति का चुनाव।
- **Canada :** Strong Centre, Advisory jurisdiction. / सशक्त केंद्र, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी अधिकार क्षेत्र।
- **Australia :** Concurrent List, Trade freedom. / समवर्ती सूची, व्यापार की स्वतंत्रता।
- **USSR :** Fundamental Duties, Socialism. / मौलिक कर्तव्य, समाजवाद।
- **France :** Liberty, Equality, Fraternity. / स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व।
- **Germany :** Emergency provisions. / आपातकालीन प्रावधान।
- **South Africa :** Amendment procedure. / संशोधन की प्रक्रिया।
- **Japan :** Procedure established by law. / कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया।



Warner & Spencer

- **The Indian Constitution is a unique synthesis of global ideas.** / भारतीय संविधान विश्व के विभिन्न विचारों का एक अनोखा समन्वय है।
- **It maintains a balance between flexibility and rigidity.** / यह लचीलापन और कठोरता के बीच संतुलन बनाए रखता है।
- **Reflects Indian conditions while incorporating world wisdom.** / यह विश्व की बुद्धिमत्ता को अपनाते हुए भारतीय परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करता है।



“The Indian Constitution is not a copy, but a carefully drafted document of wisdom.”

“भारतीय संविधान कोई कॉपी नहीं है, बल्कि समझदारी से बनाया गया एक डॉक्यूमेंट है।”

– B. R. Ambedkar



THANK

YOU

